बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 2

निराशाजनक मोड़

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के कारोबारी नतीजे मंदी और गिरते मार्जिन का रुझान दर्शाते हैं। इससे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा फरवरी में प्रस्तुत नीतिगत समीक्षा में जताई गई आशंका सही प्रतीत होती है। उस वक्त आरबीआई ने वाहनों की कम होती बिक्री, पूंजीगत वस्तुओं के कमजोर उत्पादन, औद्योगिक गतिविधियों में धीमेपन, हवाई यात्रियों में आ रही कमी आदि का जिक्र करते हुए कहा था कि आर्थिक गतिविधियों में धीमापन आ सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने अब तक तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली 2,338 कंपनियों का विश्लेषण किया। पाया गया कि सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा और दैनिक उपभोग की उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। धातु और खनन क्षेत्र का प्रदर्शन ठीक रहा, हालांकि भविष्य में इस क्षेत्र को कुछ समस्या आ सकती है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां गहरे दबाव में बनी हुई हैं।

उक्त कंपनियों का समेकित शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से 28 फीसदी कम था। राजस्व में 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जो दूसरी तिमाही के 19.6 फीसदी के इजाफे से कमजोर थी। अपवाद उत्पादों का समायोजन करने पर शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 2.2 फीसदी अधिक था। अगर तेल एवं गैस तथा वित्तीय (बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समेत) जैसे अस्थिर क्षेत्रों को अलग करके देखा जाए तो शेष 2,005 कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 39.7 फीसदी घटकर मात्र 47,500 करोड़ रुपये रह गया। यह बीते तीन वर्षों का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। कुल मिलाकर 701 कंपनियों को घाटा सहन करना पड़ा। जिन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा उनमें टाटा मोटर्स, वोडाफोन आइडिया, पुंज लॉयड और अदाणी पावर जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों का खर्च राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ा। परिचालन मार्जिन भी 3 फीसदी घटकर 12.9 फीसदी रह गया।

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का राजस्व 16 फीसदी बढ़ा। हालांकि उनका शुद्ध मुनाफा केवल 6.7 फीसदी ही बढ़ा। ऐसा कमजोर रुपये की वजह से हुआ। धातु और खनन क्षेत्र के मुनाफे में 32 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। परंतु वैश्विक जिंस कीमतों में चीन की मंदी के कारण जनवरी-फरवरी में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह मार्जिन स्थायी नहीं रहने वाला। औषधि उद्योग कई मोर्चों पर दबाव का शिकार है क्योंकि अमेरिकी औषधि प्रशासन निरंतर निर्यात इकाइयों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। इतना ही नहीं बड़ी तादाद में दवाइयां मूल्य नियंत्रण के दायरे में हैं। तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए भी यह तिमाही कठिनाई भरी रही। कच्चे तेल की कीमतें अक्टूबर और नवंबर में ऊंची बनी रहीं, दिसंबर में अवश्य उनमें गिरावट आई। हालांकि संयुक्त राजस्व में 34 फीसदी का इजाफा हुआ लेकिन शुद्ध राजस्व 16.6 फीसदी गिरा। अहम वित्तीय क्षेत्र में जिन बैंकों ने अब तक नतीजे घोषित किए हैं, उनकी ऋण वृद्धि की दर 15 फीसदी रही और उनका संयुक्त शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही के 6,000 करोड़ रुपये के घाटे से सुधरकर 900 करोड़ रुपये के फायदे वाला हो गया। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को शुद्ध नुकसान हुआ लेकिन कह सकते हैं कि बुरा वक्त बीत चुका है। एनबीएफसी का राजस्व स्थिर रहा और शुद्ध मुनाफा 11.7 फीसदी गिरा।

निष्कर्ष यही है कि बड़ी खपत में धीमापन आया है और पूंजीगत वस्तुओं की मांग में कमी बताती है कि निवेश भी कमजोर हुआ है। ग्रामीण खपत को कम खाद्य कीमतों ने प्रभावित किया। सरकारी व्यय चीजों को ठीक रखने में मददगार हुआ है। चुनाव संबंधी व्यय निजी खपत बढ़ा सकता है लेकिन यह देखना होगा कि यह गिरावट चक्रीय है या मंदी बड़ी ढांचागत वजहों से आ रही है।

अजय मोहंती

डेट और इक्विटी बाजार के बीच का संबंध

डेट बाजार के उभार के बीच शेयर बाजार में निवेश करने वालों को कुछ समय यह समझने में भी लगाना होगा कि डेट बाजार कंपनियों को लेकर उनकी क्या दृष्टि है। इस संबंध में अपनी राय रख रहे हैं **आकाश प्रकाश**

हाल तक अधिकांश शेयर बाजार निवेशक स्थानीय डेट बाजारों को शायद ही तवज्जो देते थे। देश में डेट बाजार काफी हद तक अविकसित थे। सरकारी प्रतिभूतियों से परे इनमें कारोबार बहुत कम होता था। अधिकांश कारोबारी उधारी या तो बैंकों के जरिये ली जाती थी या फिर विदेश से जुटाई जाती। कॉर्पोरेट बॉन्ड में खुदरा भागीदारी नाममात्र की होती थी।

बीते पांच-सात वर्ष में तस्वीर काफी हद तक बदल गई। बचत के बढ़ते वित्तीयकरण, डेट में आवक, म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी आदि सभी में इजाफा हुआ है। विदेशी निवेश की उदार सीमा के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी डेट बाजार में अहम हो गए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां खुदरा निवेशकों को प्रत्यक्ष तौर पर बॉन्ड जारी कर सकती हैं। इस सिलसिले में हजारों करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करना आम बात है। यह डेट बाजार में एक बड़ा बदलाव है।

आगे चलकर इनका आकार और व्यापक होगा क्योंकि घरेलू निवेशक अचल संपत्ति और सोने के बजाय परिसंपत्ति आवंटन के मामलों में इक्विटी और डेट पर ध्यान दे रहे हैं। कह सकते हैं कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद इसमें आगे और मजबूती ही आएगी। एक मजबूत और सक्रिय डेट बाजार की स्थापना के बाद अब हमें इनके बीच का संबंध और एक दूसरे पर इनका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है।

एनबीएफसी क्षेत्र अभी एक संकट से गुजरा है। इसकी प्रमुख वजह आईएलऐंडएफएस डिफॉल्ट है। इसके चलते संस्थागत डेट निवेशकों ने एनबीएफसी के प्रति अपना जोखिम खत्म कर दिया। ऐसे जोखिम वाले कई फंड ने परिपक्वता प्रपत्र को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। जो एनबीएफसी डेट फंड तक पहुंच बनाने में सफल थे उनको ऊंची दर चुकानी पड़ी। एनबीएफसी को ऋण के लिए वापस बैंकों का रुख करना पड़ा या अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी।

एनबीएफसी के प्रति डेट बाजार के जोखिम से बचने ने इनमें से अधिकांश वित्तीय संस्थानों के वृद्धि और मुनाफे के पूर्वानुमान पर असर डाला। इक्विटी बाजार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिकांश एनबीएफसी के गुणक कम कर दिए। इक्विटी निवेशक को कई तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है, भले ही उसके पास किसी भी एनबीएफसी का शेयर हो। डेट बाजार के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति का असर स्टॉक के सूक्ष्म विकास पर भी पड़ा। डेट बाजार बुनियादी बातों का संचालन भी करते हैं। अगर आप जोखिम से बचने की समझ नहीं रखते तो आपका पैसा गंवाना तय है, भले ही आपके पास किसी भी एनबीएफसी के शेयर हों।

दूसरा मामला एस्सेल समूह का है। प्रवर्तक समूह और शेयरों की बदौलत होल्डिंग कंपनी के नकदीकरण के चलते शेयर कीमतों में भारी गिरावट आई। ज़ी के शेयर 35 फीसदी तक गिर गए। यह तब हुआ जबकि कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा था।

शेयर कीमतों में गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि शेयरों की विसंगतिपूर्ण बिक्री की आशंका बरकरार है। इक्विटी निवेशक का यह अधिकार है कि वह बुनियादी चीजों के बारे में जाने लेकिन इसके बावजूद डेट बाजार डिफॉल्ट को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यहां एक बार फिर शेयर बाजार, डेट बाजार से संचालित होता है। अगर डेट बाजार शिथिल होता है तो शेयर बाजार में उछाल आएगी। डेट बाजार की समझ की कमी और उनकी चिंता उपरोक्त दोनों ही अवसरों पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

डेट बाजार का विकास और उनका बढ़ता आकार अच्छी चीज है और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऋण के जोखिम का बंटा हुआ होना सकारात्मक बात है और इससे वित्तीय तंत्र मजबूत होगा। ऋण संबंधी निर्णयों का विकेंद्रीकरण लक्षित ऋण की संभावना को कम करता है। हमने अभी जैसे ऋण चक्र का सामना किया है, वैसा ही एक और दौर हम नहीं झेल सकते। उस दौर में बैंकों की फंसी हुई परिसंपत्ति उनकी कारोबारी पुस्तिका के 30 फीसदी तक पहुंच गई थी।

अलबत्ता कुछ मसले हैं जिन पर ध्यान देना होगा। मेरा मानना है कि डेट की आवक उतनी खुदरा नहीं है जितनी कि इक्विटी फंड में एसआईपी की आवक है। कम से कम 10 से 15 बड़े कॉर्पोरेट ट्रेजरी को डेट फंड पर विसंगतिपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। अगर ये बड़े कॉर्पोरेट ट्रेजरी यह तय कर लें कि वे किसी खास जारीकर्ता से दूर रहेंगे तो अधिकांश फंड उस पेपर से बाहर निकल जाएंगे। इसके वृहद आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एनबीएफसी फंडिंग संकट के वक्त देखने को मिला। उस वक्त कई फंड को अपनी एनबीएफसी जोखिम कम करने पर मजबूर होना पड़ा। इन तमाम बातों को देखते हुए इस बात पर संदेह हो सकता है कि आखिर मौजूदा बाजार ढांचा कितना स्वस्थ है। एक अन्य मसला रेटिंग एजेंसियों का है। उनकी छवि भी कोई ठीक नहीं है। देश में ढेर सारी रेटिंग एजेंसियां हैं और उनकी गुणवत्ता मिलीजुली है। आईएलऐंडएफएस की रेटिंग एक महीने में ही 'एए' से डिफॉल्ट कैसे हो गई। रेटिंग करने का तरीका क्या है? रेटिंग एजेंसियां अक्सर मौजूदा हकीकत से समायोजन के मामले में बाजार से पीछे रहती हैं। रेटिंग एजेंसियां इक्विटी बाजार के नजरिये को ध्यान में नहीं रखतीं। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी रेटिंग 'एएए' है लेकिन बाजार को उन पर भरोसा नहीं है। इक्विटी बाजार और रेटिंग एजेंसियों के बीच की यह असंबद्धता बाजार के आवंटन पर बुरा असर डाल सकती है। अगर रेटिंग एजेंसी बाजार में भरोसा गंवा देती है तो यह बात बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। बाजार पूरी तरह ठप हो सकता है। एक बार रेटिंग की प्रासंगिकता समाप्त होने के बाद बाजार का कारोबारी दायरा सीमित हो जाएगा। ऐसा जोखिम कोई भी नहीं लेना चाहता।

डेट फंड सही कीमतों पर कारोबार कर रहे हैं या नहीं इसे लेकर भी शुबहा हमेशा बरकरार रहता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इसके लिए दिशा निर्देश तय किए हैं लेकिन फिर भी कुछ संदेह बरकरार हैं। हो सकता है यह केवल सोच का मसला हो लेकिन ऐसा सोच मौजूद तो है। हमने इस वजह से भी डेट फंड में सुदृढ़ीकरण देखा है। देश में डेट बाजारों का उभार अच्छी बात है। देश के लिए मजबूत, नकदीकृत डेट बाजार आवश्यक हैं। एक इक्विटी निवेशक के रूप में हमें उन कंपनियों को लेकर डेट बाजार के रुख को समझना होगा जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा करना अहम है क्योंकि हमने देखा है कि डेट बाजार बहुत आसानी से हमारी बुनियादी परिकल्पना में सेंध लगा सकते हैं।

कश्मीर के हालात से निपटने की चुनौती हुई और कठिन

नीति नियम

मिहिर शर्मा

कश्मीर घाटी के इतिहास के सबसे घातक हमले के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा करके हम यह देख सकते हैं कि भविष्य में क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम बातें बहुत परेशान करने वाली हैं।

सबसे पहली बात तो यह कि 2014 के बाद से घाटी में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसकी कई वजह हैं लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत सरकार ने 2014 के पहले के 10 वर्षों में हासिल लाभ को गंवा दिया। सरकार ने अधिक से अधिक कश्मीरियों को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के बजाय, कश्मीर को एक राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया।

ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले घाटी स्वर्ग जैसी थी, लेकिन तब से अब तक हिंसा की घटनाओं में जो इजाफा हुआ है, वह आंकड़ों में स्पष्ट नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद के समक्ष आतंकवाद के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनमें निरंतर इजाफा नजर आया है। वर्ष 2014 में जहां 222 आतंकी घटनाएं हुई थीं वहीं, 2018 में इनकी तादाद 614 हो गई। 2014 में जहां 47 सुरक्षा जवान शहीद हुए थे, वहीं 2017 में 80 और 2018 में 91 जवानों की मृत्यु हुई।

जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई, तो उसने नियंत्रण रेखा पर लंबे समय से जारी संघर्षविराम से अलग रुख अख्तियार किया। इसका उद्देश्य घुसपैठ का मुकाबला करना था। इससे आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई और न ही असली समस्या दूर हुई। यही कारण है कि एक बार फिर कश्मीरी युवा बंदूक उठाते नजर आ रहे हैं। यह बात सन 1990 के दशक की याद दिलाती है जब कश्मीरी युवाओं का हथियार उठाना आम होता था। विदेशी आतंकियों को लेकर चिंतित होने के बजाय हमें स्थानीय युवाओं में बढ़ती कट्टरता की चिंता अवश्य करनी चाहिए। पुलवामा में कार बम से हमला करने वाला 20 वर्षीय युवा भी ऐसे ही लोगों में से एक था। देश के युवाओं में आतंक के प्रति झुकाव दूसरा बिंदु है। तीसरी चिंता है इस्लामिकों की रणनीतियों में आ रहा बदलाव। इन नीतियों को आसानी से बदला जा सकता है। दुनिया भर के उपद्रवियों और आतंकियों के कार्य व्यवहार का अनुकरण करके ऐसा किया जा सकता है। पुलवामा हमले के बारे में खुफिया जानकारी थी कि यह सीरिया के कार बम हमलों की शैली में किया जा सकता है। कश्मीर में ऐसे आत्मघाती हमले बहुत कम हुए हैं और इस आकार का कार बम हमला तो कभी नहीं। हालांकि जैश-ए-मोहम्मद ने सन 2000 के दशक में श्रीनगर के बादामी बाग कैंट में ऐसा ही एक हमला किया था। मौत के बाद जारी हमलावर का वीडियो भी काफी हद तक पश्चिम एशिया के इतिहास की याद दिलाता है जहां वह तालिबान को अपनी प्रेरणा बताता है और अमेरिका की हार की बात करता है। आईईडी और कार बम तथा आत्मघाती हमलावरों से भरी घाटी, उससे बिल्कुल अलग है जिसका सामना सुरक्षा बलों को अब तक करना पड़ता आया है।

चौथी बात आतंकियों की रणनीति भी बदल रही है। जिहादियों ने अब खासतौर पर सेना या पुलिस बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आम नागरिकों की सहानुभूति अब उनको सन 1990 के दशक की तुलना में अधिक मिल रही है। धार्मिक कट्टरपंथ में लगातार इजाफा हो रहा है और स्थानीय स्तर पर धार्मिक परंपराओं का स्थान अब कहीं अधिक कट्टर और शून्यवादी विचार ले रहे हैं जो पश्चिम एशिया से आयात किए गए हैं। यानी सेना और अर्द्धसैनिक बलों के सामने आगे काफी मुश्किल वक्त आने वाला है। सैन्य बल पहले ही यह शिकायत करते रहे हैं कि आम नागरिकों की भीड़ उन इलाकों के बचाव के लिए घेरेबंदी करती है जहां कथित तौर पर आतंकियों के छिपे होने की आशंका होती है। आतंकियों से लड़ाई एक बात है, उपद्रवियों से निपटना कहीं अधिक मुश्किल हो सकता है और एक बड़ी आबादी से निपटना बेहद मुश्किल भरा हो सकता है।

पांचवीं बात, पड़ोस में जो कुछ घट रहा है, उसे भी एकदम आसानी से महसूस किया जा सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से हड़बड़ी में बाहर निकलने का ऐलान किया जो खतरनाक रूप से मूर्खतापूर्ण बात है। इससे दुनिया भर के जिहादियों को वैसी प्रेरणा मिलेगी जैसी मुजाहिदीन के हाथों तत्कालीन सोवियत संघ की हार से मिली थी। इस संभावित विदाई की बात ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान का उत्साह बढ़ा दिया। चीन की ओर से मिल रहा समर्थन तो है ही। पिछली बार पाकिस्तान समर्थक जिहादियों को तीन दशक पहले छूट मिली थी जब एक महाशक्ति का अंत हुआ था। हमें इस आशंका से डर लगना चाहिए कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर दबाव कम होने का क्या असर हो सकता है?

छठी बात, कश्मीर पर तो पाकिस्तान में भी उतनी अधिक बातचीत नहीं होती है। फिलहाल पाकिस्तान अपनी क्रिकेट लीग और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त है। जानकारी के मुताबिक उनकी यात्रा के लिए 3,500 कबूतर खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान में कश्मीर आज उस कदर सुर्खियों में नहीं है जैसा कि वह कुछ दशक पहले हुआ करता था। परंतु इसके बावजूद वहां घरेलू राजनीति में कश्मीर के मुद्दे के इस्तेमाल में आई कमी का कोई लाभ उठाने का खास प्रयास नहीं किया गया गया है।

सातवां, भारत में कश्मीर एक जीवंत राजनीतिक मसला है। वह भी पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बनकर उभरा है। सन 1990 के दशक में भारत को उपद्रवियों से निपटना था और वह यह काम बिना राष्ट्र की मर्दवादी छवि की चिंता किए कर सकता था। अब कश्मीर का इस्तेमाल एक रूपक के रूप में किया जाता है।

हमारा सामना अब सन 1990 के दशक की अशांति जैसी परिस्थितियों से नहीं है। तमाम तरह के कुप्रबंधन, बढ़ते कट्टरपंथ और राजनीतिकरण के कारण खतरा आज कई गुना बढ़ चुका है।

कानाफूसी

सीट का झगड़ा

हिंदुस्तान अवाम मोर्चा- सेक्युलर (एचएएम-एस) के नेता जीतन मांझी, जो कुछ समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, उन्हें लग रहा है कि उन्हें महागठबंधन में उचित तवज्जो नहीं मिल रही है। इन दिनों ये अटकलें जोरों पर हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को महागठबंधन में एचएम-एस से अधिक सीट मिल सकती हैं। मांझी का कहना है कि वह अपनी पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में यह तय करेंगे कि उनके सामने अन्य क्या राजनैतिक विकल्प शेष हैं क्योंकि महागठबंधन में उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। जब उनसे यह पूछा गया कि उनके पास क्या संभावित विकल्प हैं तो मांझी ने कहा कि वह इस विषय पर कोई सार्वजनिक चर्चा करना उचित नहीं समझते। मांझी ने कहा, 'हमारे दल को कुशवाहा की पार्टी से अधिक सीट मिलनी चाहिए, आखिरकार हम महागठबंधन से उनकी पार्टी की तुलना में काफी पहले से जुड़े हुए हैं।'

अगला प्रधानमंत्री कौन?

कुछ नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहभंग हो चुका है। लेकिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को कभी जाहिर नहीं किया है। हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक बैठक में सिंह लखनऊ से इराक के नजफ शहर की सीधी उड़ान की शुरुआत के लिए वहां पहुंचे थे। नजफ शिया समुदाय का तीर्थ स्थल है। उन्होंने उड़ान का पहला पास सैयद जफर असगर रिजवी को एक सार्वजनिक समारोह में सौंपा जो शिया समुदाय के एक धार्मिक नेता हैं। उन्होंने कहा मैं चुनाव में जीतूं या हारूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल मानवता की सेवा करना चाहता हूं। इस पर रिजवी ने कहा, 'मैं सन 2004 से लगातार नागर विमानन मंत्रियों से यह मांग कर रहा था कि वे ऐसी उड़ान शुरू करें, अब राजनाथ सिंह ने यह काम आसान किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह भारत के प्रधानमंत्री बनें।' लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा,'और नरेंद्र मोदी नहीं'।

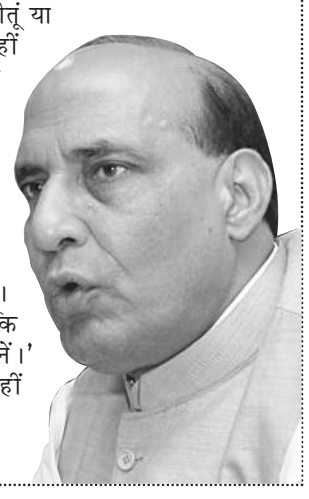

आपका पक्ष

आतंकवाद पर लगाम लगाना जरूरी

हमें पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश मिला है जो रह-रहकर हमें दहशतगर्दी का दर्द देता रहता है। जम्मू-कश्मीर में हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से लदी गाड़ी से सीआरपीएफ की बस को टक्कर मार दी जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले से जाहिर है कि आतंकियों ने काफी सोच-समझकर लंबी तैयारी के बाद अपनी इस करतूत को अंजाम दिया है। इससे एक बात तो साफ है कि आतंकियों को सीआरपीएफ की गतिविधियों की जानकारी पहले से थी। वैसे जब सुरक्षा बलों का काफिला निकलता है तो आम गाड़ियों को रोक दिया जाता है और उन पर नजर रखी जाती है। सवाल उठता है कि इतना ज्यादा विस्फोटक आत्मघाती हमलावर के हाथ कैसे लगा? निश्चित रूप से यह सीमापार से आया है और इस स्तर पर निगरानी में कोई बड़ी चूक हुई है। आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे पहले एक पुख्ता सुरक्षा तंत्र की जरूरत है। सुरक्षा बलों के काफिले जम्मू-कश्मीर में आते-जाते रहते हैं लेकिन इस तरह का हमला पहली बार ही हुआ है। इस घटना पर देश भर में गुस्सा है जो स्वाभाविक है लेकिन यह वक्त संयम रखने का है। किसी को भी ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे देश का माहौल बिगड़े। आतंकवाद से पूरे राष्ट्र को मिल कर लड़ना है और साजिश रचने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा भी देनी है। इसके लिए हमें कई मोर्चों पर पहल करनी होगी। सबसे पहले उन सबसे संवाद बनाना होगा जो इस लड़ाई में हमारे सहयोगी हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत अन्य आतंकियों की सूची को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वैश्विक सूची में शामिल करने का आग्रह किया है और विश्व बिरादरी से अपील की है कि वह पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करे। चीन ने पुलवामा हमले की निंदा तो की है पर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में डालने की भारत की अपील का समर्थन करने से मना कर दिया है। हमें इस कोशिश को आगे भी जारी रखना होगा।

अनिल सक्सेना, गया, बिहार

पुलवामा आतंकी हमले जैसी घटनाएं रोकने के लिए कई मोर्चों पर पहल करे भारत

आतंक पर चीन किसके साथ

पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन की दोहरी नीति सामने आ गई है। हालांकि चीन ने इस आतंकी हमले की निंदा तो की है लेकिन मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने से साफ मना कर दिया है। वैश्विक मंच पर चीन आतंकवाद के मसले पर भारत के साथ होने का दिखावा करता है लेकिन पीठ पीछे भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आतंकवाद को पोषित करता है। चीन ने 2016 में भी सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में मसूद अजहर का नाम डलवाने को लेकर भारत के प्रयास में अड़ंगा डालकर इसे रुकवा दिया था। इसके बाद जब भारत ने मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की अपील की तब भी चीन की तरफ से नकारात्मक रुख दिखाया गया था। जाहिर है आतंकवाद के मुद्दे पर वह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है।

शोभन चौधरी, कोलकाता

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।